

## प्रारंभिक परीक्षा

### हानि एवं क्षति कोष से अमेरिका का हटना

#### संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन आपदाओं से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

#### हानि एवं क्षति कोष(Loss & Damage Fund) के बारे में -

- यह एक वित्तीय तंत्र है जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आर्थिक और गैर-आर्थिक हानि और क्षति से निपटने में मदद करता है।
- स्थापना: मिस्त्र के शर्म अल-शेख में UNFCCC के COP-27 (पार्टियों का सम्मेलन) में
- प्रबंधन: विश्व बैंक (4 वर्षों के लिए अंतरिम ट्रस्टी)
- 2025 तक इस कोष के लिए 750 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया गया है।
- उद्देश्य:
  - कमज़ोर देशों को सहायता प्रदान करना
  - जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति का समाधान करना और उसकी भरपाई करना
  - किसी आपदा के तुरंत बाद मानवीय सहायता का वित्तपोषण
  - जलवायु परिवर्तन के मध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों को संबोधित करना
- हानि एवं क्षति कोष बोर्ड:
  - यह कोष एक बोर्ड द्वारा संचालित होता है जो धन आवंटित करने, परियोजनाओं को मंजूरी देने और नीतियां निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
  - बोर्ड की आधिकारिक स्थापना 2023 में दुबई में COP-28 द्वारा इसके परिचालन ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद की गई थी।
  - संरचना: विकसित और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 सदस्य।

#### UNFCCC

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन(UNFCCC) एक संधि है जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करती है।
- इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- पार्टियों का सम्मेलन(COP) UNFCCC का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है।
  - इसकी बैठक हर साल आयोजित की जाती है।

स्रोत: [Indian Express - L& D Fund](#)

## वैश्विक मसाला बाज़ार में भारत की स्थिति

### संदर्भ

भारत दुनिया में विविध प्रकार के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद वैश्विक मसाला बाजार में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है।

### भारत में मसाला उत्पादन -

- भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जो वैश्विक मसाला उत्पादन में 75% का योगदान देता है।
- भारत काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया और केसर जैसे विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन करता है।
- भारत में उत्पादित 85% मसालों की खपत घरेलू स्तर पर होती है।
- भारत में शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य:
  - मध्य प्रदेश (2) राजस्थान (3) गुजरात (4) कर्नाटक (5) तेलंगाना।

### विश्व मसाला संगठन (WSO)

- WSO एक गैर-लाभकारी संगठन है जो किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एक साथ लाता है।
- इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। (मुख्यालय- कोच्चि, केरल)
- WSO अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच के साथ राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन (NSC) की मेजबानी करता है।
- फोकस क्षेत्र:
  - स्थिरता - पर्यावरण के अनुकूल मसाला खेती को बढ़ावा देता है।
  - खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण - वैश्विक मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।
  - प्रशिक्षण और अनुसंधान - खेती की तकनीक और कीटनाशक प्रबंधन में सुधार के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के साथ काम करता है।

### वैश्विक मसाला बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी -

- मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद, वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी (2024 में \$14 बिलियन) केवल 0.7% है।
  - मसाला एक सूखे पौधे के भाग जैसे बीज, छाल या फल को कहा जाता है जिसका उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।
  - प्रसंस्कृत मूल्यवर्धित मसाले (सीज़निंग) विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण है, जिसमें मसाले, जड़ी-बूटियाँ, नमक और अन्य स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ शामिल हैं।
- इसके विपरीत, चीन के पास बाजार का 12% हिस्सा है, जबकि अमेरिका के पास 11% हिस्सा है।
- मसाला बाजार में कम हिस्सेदारी का कारण:
  - भारत मुख्य रूप से कच्चे मसालों का निर्यात करता है, जबकि चीन और अमेरिका जैसे देश प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित मसालों (सीज़निंग) पर हावी हैं।
  - सीज़निंग क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
- मसाला निर्यात में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता:
  - वर्तमान में भारत के मसाला निर्यात का केवल 48% ही मूल्य-संवर्धित उत्पाद हैं।
  - शेष 52% साबुत मसालों के रूप में बेचे जाते हैं।
  - लक्ष्य:
    - मूल्य-संवर्धित मसाला निर्यात को 70% तक बढ़ाना।

- 2030 तक 10 बिलियन डॉलर का निर्यात राजस्व प्राप्त करना (**भारतीय मसाला बोर्ड का लक्ष्य**)।
- **उभरते प्रतिस्पर्धी:** वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, चीन और अफ्रीकी देश अपने मसाला उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं।

### भारतीय मसाला बोर्ड -

- **स्थापना:** 1987 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन (मुख्यालय - कोच्चि, केरल)।
- यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसका गठन इलायची बोर्ड (1968) और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद (1960) को मिलाकर किया गया था।
- **महत्वपूर्ण कार्य:**
  - **निर्यात संवर्धन** - भारत के वैश्विक मसाला व्यापार को बढ़ाना।
  - **गुणवत्ता नियंत्रण** - कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और गुंटूर जैसे शहरों में परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित करना।
  - **किसान सहायता** - कीटनाशक प्रबंधन, स्वच्छता और टिकाऊ खेती पर प्रशिक्षण।
- यह "फ्लेवरइट(Flavourit)" का प्रबंधन करता है - जो उपभोक्ताओं को सीधे प्रीमियम मसाले बेचने वाला एक आउटलेट है।

स्रोत: [The Hindu - Spices production](#)



## अमेरिकी रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व

### संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व और एक अमेरिकी डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

### अमेरिकी रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व (SBR) के बारे में -

- SBR बिटकॉइन का एक नया स्थापित राष्ट्रीय रिजर्व है।
- यह सरकार द्वारा रणनीतिक संपत्ति के रूप में रखा गया पहला आधिकारिक बिटकॉइन रिजर्व है।
- रिजर्व का उपयोग बिक्री या व्यापार के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय यह अमेरिकी सरकार के लिए मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करेगा।
- रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व का उद्देश्य:
  - विकेंद्रीकृत डिजिटल परिसंपत्तियों को धारण करके अमेरिकी वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करना।
  - वैश्विक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में अमेरिका को एक अग्रणी के रूप में स्थान देना।
  - बिटकॉइन की समय से पहले बिक्री को रोकना, जिससे करदाताओं को \$17 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है।
  - जब्त बिटकॉइन होल्डिंग्स का उचित प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रपति ट्रम्प ने बिटकॉइन के अलावा चार अन्य सिक्कों का भी उल्लेख किया है जो डिजिटल परिसंपत्ति भंडार का हिस्सा होंगे - एथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो।

### अमेरिकी रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व कैसे काम करेगा?

- बिटकॉइन होल्डिंग्स का स्रोत: रिजर्व बिटकॉइन नहीं खरीदेगा, लेकिन निम्नलिखित बिटकॉइन के साथ पूंजीकृत किया जाएगा:
  - अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और न्याय विभाग जैसी एजेंसियों द्वारा आपराधिक या सिविल संपत्ति जब्ती मामलों में जब्त किया गया।
  - बिटकॉइन के स्वामित्व वाली अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों से स्थानांतरित किया गया।
  - ऐसा अनुमान है कि अमेरिकी सरकार के पास वर्तमान में 200,000 बीटीसी हैं।
- रिजर्व का प्रबंधन: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग रिजर्व की देखरेख करेगा।
- बिटकॉइन बेचने की नीति:
  - अमेरिका अपने रिजर्व से बिटकॉइन नहीं बेचेगा।
  - सोने के भंडार के समान दीर्घकालिक आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में बनाए रखा जाएगा।
  - SBR से अलग यूएस डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल में अन्य क्रिप्टोकॉइन्स होंगी जिन्हें बेचा जा सकेगा।

### रणनीतिक रिज़र्व क्या है?

- रणनीतिक रिज़र्व किसी महत्वपूर्ण संसाधन का भंडार होता है जिसे संकट या आपूर्ति में व्यवधान के समय जारी किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए अमेरिकी रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व, विश्व में आपातकालीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, जिसे 1973-74 में अरब तेल प्रतिबंध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के चरमरा जाने के बाद 1975 में कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।

### अन्य देशों के रणनीतिक भंडार -

- **भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR):** तेल भंडारों का संग्रह जिसका उपयोग सरकार वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति व्यवधानों का जवाब देने के लिए कर सकती है।
  - **भारत के SPR की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल की है।**
  - **स्थान:** विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर।
  - **निर्माणाधीन:** चंडीखोल (ओडिशा) और पादुर-II (कर्नाटक)
- **कनाडा:** इसके पास मेपल सिरप का विश्व का एकमात्र रणनीतिक भंडार है।
- **चीन:** इसके पास पेट्रोलियम, धातु, अनाज और यहां तक कि पोर्क उत्पादों के रणनीतिक भंडार भी हैं।

स्रोत: [Indian Express - Bitcoin Reserve](#)



## ट्रम्प द्वारा टैरिफ़ की वापसी और उसका प्रभाव

### संदर्भ

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको पर उच्च आयात कर (टैरिफ) लगाया, लेकिन 48 घंटे के भीतर उसे वापस ले लिया।

### अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक मुद्दे -

- अमेरिकी अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर करती है:
  - अमेरिका घरेलू उत्पादन से ज़्यादा उपभोग करता है, जिससे व्यापार घाटा होता है।
  - अमेरिका में व्यापार घाटा इसलिए है क्योंकि वह निर्यात से ज़्यादा आयात करता है।
- ऐसा क्यों होता है?
  - अमेरिका में उच्च श्रम लागत कुछ वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को अक्षम बनाती है।
  - सस्ते श्रम वाले देशों (जैसे, चीन, मैक्सिको, वियतनाम) को तुलनात्मक लाभ होता है।
  - आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर उच्च आयात खपत की अनुमति देता है।
- टैरिफ़ इस समस्या को हल नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका को हमेशा मांग को पूरा करने के लिए अधिक वस्तुओं का आयात करना होगा।
- ट्रम्प द्वारा अपने पहले कार्यकाल में हस्ताक्षरित USMCA (उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता) अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच व्यापार को नियंत्रित करता है।
  - USMCA पर नवंबर, 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसने NAFTA (उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता) की जगह ली।
  - कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ का मौजूदा अधिरोपण इस मुक्त व्यापार समझौते का उल्लंघन है। इससे अमेरिका के व्यापार सौदों पर सवालिया निशान लग गया है।

### टैरिफ का भुगतान कौन करता है, इस बारे में गलत धारणा -

- ट्रम्प का दावा है कि टैरिफ का भुगतान विदेशी देशों द्वारा किया जाता है → गलत
- वास्तविकता:
  - अमेरिकी आयातक (अमेरिकी कंपनियां) माल आने पर टैरिफ का भुगतान करती हैं।
  - बढ़ी हुई लागत का बोझ बढ़ी हुई कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाला जाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैरिफ का प्रचलन क्यों कम हो गया?
  - क्योंकि वे अंततः घरेलू रोजगार को बढ़ावा दिए बिना उपभोक्ता लागत में वृद्धि करते हैं।

स्रोत: [Indian Express - Tariff Threat](#)

## निवेश द्वारा वानुअतु की नागरिकता कार्यक्रम

### संदर्भ

पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा कर दिया है और वानुअतु की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

### निवेश द्वारा नागरिकता (CBI) के बारे में -

- वानुअतु 83 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है, जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 1,300 किलोमीटर में फैला हुआ है।
- CBI व्यक्तियों को किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान देकर उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- यह योजना आसान वैश्विक गतिशीलता, कर लाभ और अपतटीय वित्तीय सेवाओं की तलाश करने वाले धनी व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय है।
- ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स के अनुसार, वानुअतु सबसे तेज़ और सरल CBI कार्यक्रम प्रदान करता है।
- लागत: एक व्यक्ति के लिए नागरिकता की लागत \$135,500 और \$155,500 (₹1.18 करोड़ से ₹1.35 करोड़) के बीच है।
  - 2019 में, बीबीसी ने बताया कि पासपोर्ट की बिक्री वानुअतु के राजस्व का लगभग 30% हिस्सा है।
- माल्टा, तुर्की, मोंटेनेग्रो, एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका और मिस्र जैसे देश भी इसी तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं।
- वानुअतु नागरिकता के लाभ:
  - वीज़ा-मुक्त यात्रा: 2025 तक, वानुअतु पासपोर्ट 113 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।
  - टैक्स हेवन स्थिति: वानुअतु को शून्य-कर क्षेत्राधिकार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत लाभ कर, विरासत कर, संपत्ति कर आदि नहीं है।



स्रोत: [Indian Express - Golden Passport Scheme](#)

## भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि

### संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने तहव्वुर हुसैन राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।

### भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (1997) के बारे में -

- इसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए 1997 में हस्ताक्षरित किया गया था।
- कोई अपराध प्रत्यर्पण योग्य है यदि वह दोनों देशों में एक वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है (दोहरी आपराधिकता सिद्धांत)।
- राजनीतिक अपराध प्रत्यर्पण योग्य नहीं हैं। हालाँकि, कुछ अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाता है, जैसे: राष्ट्रध्वज की हत्या, अपहरण, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध।
- प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है यदि:
  - व्यक्ति को नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विश्वासों के आधार पर उत्पीड़न का जोखिम है।
  - अपराध सैन्य प्रकृति का है।
  - अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, जब तक कि अनुरोध करने वाला देश यह आश्वासन न दे कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।
- भारत-अमेरिका संधि के तहत प्रत्यर्पण में चुनौतियाँ:
  - धीमी प्रक्रिया: कानूनी चुनौतियों के कारण प्रत्यर्पण मामलों में अक्सर वर्षों लग जाते हैं।
    - भारत 65 भारतीय भगोड़ों की अमेरिका से प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहा है।
    - 2002 से 2018 के बीच केवल 11 प्रत्यर्पण हुए।
  - अमेरिकी अनिच्छा: कई प्रमुख भारतीय अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया है। उदाहरणार्थ,
    - डेविड हेडली - 26/11 मुंबई हमलों का साजिशकर्ता,
    - वॉरेन एंडरसन - युनियन कार्बाइड के सीईओ, भोपाल गैस त्रासदी।
  - विभिन्न कानूनी प्रणालियाँ: कुछ भारतीय आरोप प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी कानूनी मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

### प्रत्यर्पण संधियाँ बनाम प्रत्यर्पण व्यवस्थाएँ -

- प्रत्यर्पण संधि: प्रत्यर्पण के लिए दो देशों के बीच एक औपचारिक कानूनी समझौता।
  - भारत ने 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - प्रमुख देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, ऑस्ट्रेलिया।
- प्रत्यर्पण व्यवस्था: औपचारिक संधि के बिना भी प्रत्यर्पण के लिए आपसी समझ। (वर्तमान में 12 देशों के साथ)।
  - प्रमुख देश: हांगकांग, सऊदी अरब, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन।

स्रोत: [Indian Express - Extradition Treaty](#)

## इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट-2025

### संदर्भ

दूसरी इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट GIFT सिटी, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई, जिसका आयोजन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फिक्की और आईएफएससीए के सहयोग से किया।

### समिट की मुख्य बातें -

- **पहला भारतीय बैंक-निष्पादित विमान वित्तपोषण सौदा:**
  - एक्सिस बैंक GIFT सिटी IFSC में विमान वित्तपोषण लेनदेन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया।
- **विमानन वित्त में GIFT सिटी की भूमिका:**
  - GIFT सिटी भारत के पहले विमान पट्टे केंद्र (aircraft leasing hub) के रूप में उभर रहा है।
  - परंपरागत रूप से, भारत विमान वित्तपोषण के लिए बहुराष्ट्रीय बैंकों पर निर्भर था।
  - GIFT सिटी डबलिन और सिंगापुर जैसे वैश्विक पट्टे केंद्रों के विकल्प के रूप में उभर रहा है।
  - **विमानन वित्त के लिए GIFT सिटी के प्रमुख लाभ:**
    - विदेशी लीजिंग केन्द्रों पर निर्भरता कम हो जाती है।
    - भारत के विमानन क्षेत्र से आर्थिक लाभ वापस भारत में लाया जाएगा।
- **भारत के विमानन क्षेत्र का विकास:**
  - भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।
- **विकास के प्रमुख चालक:**
  - **उड़ान योजना:** 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई, इसका लक्ष्य 4 करोड़ यात्रियों को जोड़ना तथा 120 नए गंतव्यों का विकास करना है।
  - **हवाई अड्डे का विस्तार:** वर्तमान में: 149 हवाई अड्डे कार्यरत हैं।
    - **2029-30 तक:** अतिरिक्त 50 नये हवाई अड्डों की योजना बनाई गई है।
    - **2047 तक:** कुल 350 हवाई अड्डे, जिनमें 34 मेगा हवाई अड्डे शामिल हैं, जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेंगे।
- **भारत में विमान पट्टे का महत्व:**
  - विमान पट्टे पर लेना एक कानूनी समझौता है, जिसके तहत एयरलाइन या अन्य ऑपरेटर एक पट्टा कंपनी से एक निश्चित अवधि के लिए विमान किराये पर लेता है।
  - यह एयरलाइनों के लिए विमान को सीधे खरीदे बिना उसे प्राप्त करने का एक लोकप्रिय तरीका है।
  - **भारत के एयरलाइन बेड़े की वर्तमान स्थिति:** 800 विमान परिचालन में।
    - **लक्ष्य:** अगले 5 वर्षों में 1,500 विमान।

### GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी)

- यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।
- विश्व स्तरीय वित्तीय बुनियादी ढांचे वाला एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)।
- IFSCA (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) द्वारा विनियमित।
- **विमानन वित्त के लिए GIFT सिटी क्यों महत्वपूर्ण है?**
  - कोई विदेशी मुद्रा प्रतिबंध नहीं होने के कारण यह वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक है।
  - वित्तीय सेवा फर्मों के लिए कम कर दरें और विनियामक लाभ।

स्रोत: [The Hindu - Aircraft financing](#)

## समाचार में स्थान

### बारबाडोस

- हाल ही में बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस' से सम्मानित किया है।
- यह पुरस्कार बारबाडोस, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या वैश्विक शांति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- **मान्यता का कारण:** कोविड-19 महामारी के दौरान बारबाडोस को भारत की महत्वपूर्ण सहायता।



- **अवस्थिति:** दक्षिण-पूर्वी कैरेबियन सागर में एक द्वीप देश।
- बारबाडोस निकटवर्ती लेसर एंटिलीज़ द्वीपसमूह का हिस्सा नहीं है, हालांकि इसे आमतौर पर इसके साथ समूहीकृत किया जाता है।
- लेसर एंटिलीज़ कैरेबियन सागर में छोटे द्वीपों का एक लम्बा चाप है जो वर्जिन द्वीप समूह से ग्रेनेडा तक उत्तर-दक्षिण दिशा में फैला हुआ है।
- **स्वतंत्रता:** 1966 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- **गणतंत्र का दर्जा:** 30 नवंबर 2021 को गणतंत्र बन गया, जिसने ब्रिटिश राजशाही को राज्य प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के साथ बदल दिया।

स्रोत: [PIB - Barbados](#)

### लताकिया (सीरिया)

- सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) के अनुसार, सीरियाई सुरक्षा बलों ने तटीय प्रांत लताकिया में दर्जनों अलावी नागरिकों को मार डाला है।
- सीरिया की जनसंख्या: युद्ध से पहले यह लगभग 22 मिलियन थी, जो अब विस्थापन के कारण काफी कम हो गई है।
- धार्मिक संरचना: बहुसंख्यक सुन्नी मुस्लिम
  - अलावी (जनसंख्या का 10%), शिया इस्लाम की एक शाखा।
  - अन्य अल्पसंख्यकों में ईसाई, ड्रूज़ और कुर्द शामिल हैं।



- अवस्थिति: भूमध्य सागर की सीमा पर उत्तर-पश्चिमी सीरिया में एक तटीय प्रांत।
- ऐतिहासिक महत्व:
  - अलावी अल्पसंख्यक और असद परिवार का गढ़।
- रणनीतिक महत्व:
  - यह रूस के हमीमिम एयर बेस का गृह है, जो एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान है।
  - प्रमुख बंदरगाह शहर और आर्थिक केंद्र।
- सीरिया के सीमावर्ती देश: तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजरायल और लेबनान।

स्रोत: [The Hindu - Latakia](#)

### निप्रो/नीपर नदी

- रूसी सेना यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में नीपर नदी को पार करने के लिए बार-बार भारी क्षति के प्रयास कर रही है।



- यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है और यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। (2200 किमी)
- उत्पत्ति: वल्दाई हिल्स, रूस।
- प्रवाह: रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में गिरती है।
- यह यूक्रेन को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करता है, जिससे यह एक प्राकृतिक सैन्य अवरोध बन जाता है।
- युद्ध में भूमिका:
  - खेरसॉन क्षेत्र नीपर नदी के मुहाने पर स्थित है, जो इसे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।

स्रोत: [The Guardian - Dnieper](#)